JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरान परिवारों के आर्थिक चुनौतियाँ: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ इंद्र मोहन पन्त , असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग , लक्ष्मण सिंह महर परिसर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा

सारांश

कोविड-19 महामारी ने उत्तराखंड में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न किए, जिसके परिणामस्वरूप शहरी केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर रिवर्स पलायन हुआ। महामारी के प्रथम चरण में लगभग 3,57,536 श्रमिक अपने गृह क्षेत्रों में लौटे, जबकि अप्रैल–मई 2021 की दूसरी लहर के दौरान 53,092 अतिरिक्त श्रमिक वापस आए।

मुख्य शब्द : रिवर्स पलायन , प्रवासी , उत्तराखंड , कविड-19, आर्थिक स्थिति

यह अध्ययन उत्तराखंड में लौटे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों द्वारा झेली गई आर्थिक चुनौतियों को समझाता है , तथा आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का विश्लेषण करता है। यह शोध द्वितीय श्रोत पर आधारित है , जिसमें पूर्व में किये गए अध्ययन, सरकारी रिपोर्ट्स , एवं अन्य श्रोत शामिल है कि परिवारों ने संसाधनों के साझा उपयोग, निर्वाह कृषि और सरकारी राहत कार्यक्रमों पर निर्भरता के माध्यम से अनुकूलन किया। निष्कर्ष संकेत देते हैं कि संयुक्त परिवारों ने सामूहिक संसाधन साझेदारी के माध्यम से लचीलापन प्रदर्शित किया, किंतु सीमित स्थानीय रोजगार अवसरों के कारण समग्र आर्थिक पुनरुद्धार की गति धीमी रही।

प्रस्तावना

सन् 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत ने गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न किए, विशेषकर उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शहरी केंद्रों में मौसमी और निम्न-वेतन रोजगार पर निर्भर है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने अनेक प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल गांवों में लौटने के लिए विवश किया।

"उत्तराखंड में 2020 के प्रथम चरण के दौरान लगभग 3,57,536 श्रमिक अपने मूल स्थानों पर लौटे, जबकि अप्रैल–मई 2021 की दूसरी लहर के दौरान 53,092 अतिरिक्त श्रमिकों ने वापसी की"[1]। श्रमिकों की इस अचानक वापसी ने ग्रामीण उत्तराखंड में, जहाँ अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पर्यटन पर आधारित है,

विशिष्ट चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ पर्यटन क्षेत्र, यात्रा प्रतिबंधों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो गई।

यह अध्ययन इन चुनौतियों का विश्लेषण करने तथा परिवारों द्वारा अपनाई गई अनुकूलन रणनीतियों की जांच करने का उद्देश्य रखता है।

अनुसंधान उद्देश्य:

- रिवर्स प्रवसन के कारण उत्तराखंड के परिवारों द्वारा झेली गई आर्थिक चुनौतियों को समझना।
- शहरी आय के नुकसान के बाद परिवारों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की पहचान करना।
- आर्थिक अनुकूलन में सामुदायिक नेटवर्क और सरकारी समर्थन की भूमिका का मूल्यांकन करना।

अनुसंधान प्रश्न: • प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद परिवारों को किन आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

- ग्रामीण परिवेश में शहरी आय के अचानक नुकसान के प्रति परिवारों ने किस प्रकार अनुकूलन किया?
- इन अनुकूलन रणनीतियों में सामुदायिक नेटवर्क और सरकारी समर्थन की क्या भूमिका रही?

साहित्य समीक्षा

उत्तराखंड में प्रवासन के पैटर्न और प्रवासियों की आर्थिक भूमिका

उत्तराखंड लंबे समय से सीमित स्थानीय रोजगार अवसरों के कारण बाह्य-प्रवासन का अनुभव करता रहा है। "विशेषकर ग्रामीण जिलों के प्रवासी श्रमिक दिल्ली, मुंबई या राज्य के शहरी जिलों जैसे उधम सिंह नगर , हरिद्वार , देहरादून जैसे शहरों/जिलों में रोजगार की तलाश में जाते रहे हैं"[2] (बिष्ट, 2019)। इन प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि घरेलू आय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जो दैनिक आवश्यकताओं तथा कृषि निवेश का समर्थन करती रही है (पंत एवं सिंह, 2020)। **लेबर माइग्रेशन एंड रेमिटेंसिज़ इन उत्तराखंड** के अनुसार- "उत्तराखंड के लगभग 69% प्रवासी अपने परिवारों को धनराशि भेजते हैं, जिनमें अधिकांश ₹1,000–3,000 प्रतिमाह भेजते हैं। यह राशि उनकी मासिक आय का लगभग 19–31% होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की राशि इससे काफी अधिक पाई गई"[3]। इन सब कारणों से उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मनी आर्डर इकॉनमी कहा जाता है।

कोविड-19 के दौरान रिवर्स प्रवासन का प्रभाव

कोविड-19 महामारी के प्रथम लहर में 'उत्तराखंड पलायन एवं निवारण आयोग' की रिपोर्ट के अनुसार "3,57,000 से अधिक लोगों की वापसी दर्ज की गई। अप्रैल–मई 2021 की दूसरी लहर के दौरान 53,092 अतिरिक्त प्रवासी लौटे, जिन प्रवासियों में श्रमिक (कुशल एवं अकुशल), विद्यार्थी , कॉर्पोरेट कर्मचारी सभी शामिल थे क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार समाप्त हो गए और शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चरमरा गईं।

जिससे भय एवं रोजगार संकट ने इस अचानक हुई वापसी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव डाला, और अनेक परिवारों को अतिरिक्त सदस्यों का भरण-पोषण करने में कठिनाई हुई"[4]।

आर्थिक चुनौतियाँ और अनुकूलन रणनीतियाँ

"ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड में संयुक्त परिवार प्रणाली सामाजिक और आर्थिक लचीलापन का स्रोत रही है" (देसाई, 2018)[5]। महामारी के दौरान परिवारों ने आर्थिक दबावों से निपटने के लिए निर्वाह कृषि और सामुदायिक श्रम-साझेदारी जैसी पारंपरिक प्रथाओं को पुनः अपनाया। यद्यपि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के व्यापक प्रभावों का अध्ययन किया गया है, किंतु उत्तराखंड में प्रत्यावर्ती प्रवासियों द्वारा अपनाई गई विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियों पर सीमित शोध उपलब्ध है। यह अध्ययन इसी अंतर को भरने का प्रयास करता है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। पलायन एवं निवारण आयोग की रिपोर्ट , प्रवासन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित शोध-पत्रों, अकादमिक जर्नल लेखों, संदर्भ पुस्तकों तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। संकलित सामग्री का परीक्षण विषयवस्तु विश्लेषण तथा व्याख्यात्मक पद्धति के माध्यम से किया गया, जिसके आधार पर आर्थिक चुनौतियों, अनुकूलन रणनीतियों और सामाजिक लचीलेपन से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान की गई। चूंकि अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, अतः इसके निष्कर्ष उपलब्ध स्रोतों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर निर्भर हैं।

परिवारों द्वारा झेली गई आर्थिक चुनौतियाँ

• **शहरी आय का नुकसान:** प्रवासियों द्वारा अपने गृह जनपदों में आने के बाद उन्हें पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे उन्हें अपने आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा एवं इसका असर उनकी पारिवारिक स्थिति में भी पड़ा, अबेला एवं शशिकुमार(2020) ने "अपने अध्ययन में 21.1 प्रतिशत आय हानि का प्रवासियों में अनुमान बतलाया"[6], इसी तरह अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की रिपोर्ट बतलाती है "कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों (कुशल एवं अकुशल) की आय में 64 प्रतिशत की कमी देखी गयी"[7]।

• **घरेलू बोझ में वृद्धि:** कोविड-19 के दौरान शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध न होने से बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे। "सोमेश पाठक एवं मंजरी अग्रवाल ने अपने शोध पत्र 'रिवर्स माइग्रेशन एंड कोविड-19: अ स्टडी ऑन उत्तराखंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन रिवर्स माइग्रेशन' में स्पष्ट किया कि लौटे हुए प्रवासियों के कारण ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा, क्योंकि उन्हें सीमित कृषि आय के बीच अतिरिक्त सदस्यों का भरण-पोषण करना पड़ा"। इसी प्रकार IIPA(भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) की रिपोर्ट में उल्लेख है कि "लगभग 2.15 लाख लोगों की वापसी ने ग्रामीण संसाधनों और आजीविका पर दबाव बढ़ाया, जिससे घरेलू व्यय और निर्भरता अनुपात में वृद्धि हुई"[8]।

कृषि भूमि एवं स्थानीय संसाधनों पर दबाव

उत्तराखंड पलायन एवं निवारण आयोग की इनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही रुकी रही। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लौटे हुए प्रवासियों में से लगभग 33% ने कृषि, बागवानी एवं पशुपालन को आजीविका का मुख्य साधन बनाया । यह इस बात का संकेत देता है कि अतिरिक्त श्रम-शक्ति का प्रमुख समायोजन कृषि क्षेत्र में हुआ।किन्तु उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों — जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी — में औसत जोत आकार अत्यंत छोटा है और उत्पादन क्षमता सीमित है। ऐसे में कृषि क्षेत्र अतिरिक्त जनसंख्या को स्थायी रूप से समाहित करने में सक्षम नहीं रहा। इससे भूमि पर निर्भरता तो बढ़ी, परंतु आय में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो सकी। Somesh Pathak (2020) के अध्ययन के अनुसार, लौटे हुए प्रवासियों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव पड़ा — एक ओर सीमित कृषि उत्पादन और दूसरी ओर आय के वैकल्पिक स्रोतों की कमी। परिणामस्वरूप परिवारों को मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं की ओर अधिक झुकाव करना पड़ा।

इस प्रकार, रिवर्स पलायन ने उत्तराखंड की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक सीमाओं को उजागर किया। कृषि क्षेत्र ने संकट के समय अस्थायी समायोजन तो प्रदान किया, किंतु यह दीर्घकालिक समाधान सिद्ध नहीं हुआ।

रोजगार अवसरों की कमी और पुनः पलायन की प्रवृत्ति: कोविड-19 की प्रथम एवं दूसरी लहर में लौटे प्रवासियों के विश्लेषण से ज्ञात होता है , कोविड-19 की प्रथम लहर के दौरान लौटे प्रवासियों में से अधिकतर प्रवासी परिस्थियों के अनुकूल होने एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधो के हटने के पश्चात शहरों क्षेत्रों की ओर वापस चले गए और इसे एक चक्र के रूप में समझा जा सकता है।

बहु-आय स्रोतों का विकास

कोविड-19 के बाद ग्रामीण परिवारों ने एकल आय स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय बहु-आय की रणनीति अपनाई। लौटे हुए प्रवासियों ने कृषि के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, लघु व्यापार, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा स्थानीय हस्तशिल्प कार्यों को अपनाया। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग (2021) की रिपोर्ट के अनुसार, लौटे हुए प्रवासियों में स्वरोजगार और कृषि-आधारित गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

स्थानीय उद्यमिता एवं सूक्ष्म व्यवसायों की शुरुआत

कई प्रवासियों ने अपने पूर्व शहरी अनुभव और कौशल का उपयोग करते हुए स्थानीय स्तर पर छोटे उद्यम शुरू किए, जैसे — मोबाइल मरम्मत, किराना दुकान, डेयरी इकाई, टेंट हाउस सेवा, और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियाँ। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उन जिलों में देखी गई जहाँ प्रवासियों के पास सेवा क्षेत्र का अनुभव था। विभिन्न अध्ययनों में उल्लेख है कि कोविड-19 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म-उद्यम की संख्या में वृद्धि हुई (Pathak, 2020)। यह अनुकूलन रणनीति स्थानीय आत्मनिर्भरता की दिशा में संकेत करती है।

सरकारी कौशल एवं स्वरोजगार योजनाओं का उपयोग

कोविड-19 के बाद राज्य सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाईं। लौटे हुए प्रवासियों को स्वरोजगार ऋण, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ने का प्रयास किया गया। मनरेगा के माध्यम से अस्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराया गया

उपभोग व्यय में कटौती एवं जीवनशैली में परिवर्तन

आय में कमी के कारण परिवारों ने उपभोग व्यवहार में परिवर्तन किया। गैर-आवश्यक खर्चों को सीमित किया गया, स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया तथा आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव बढ़ा। कई अध्ययनों में उल्लेख है कि महामारी के दौरान ग्रामीण परिवारों ने बचत-आधारित रणनीति अपनाई और अनिश्चित भविष्य को ध्यान में रखते हुए खर्चों को नियंत्रित किया।

डिजिटल माध्यमों का सीमित उपयोग

कुछ क्षेत्रों में लौटे हुए युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएँ, ई-कॉमर्स या फ्रीलांस कार्य प्रारंभ किए। यद्यपि यह प्रवृत्ति व्यापक नहीं थी, फिर भी यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकेतक रही।

चर्चा एवं निष्कर्ष :

यह अध्ययन दर्शाता है कि संयुक्त परिवार संरचना ने आर्थिक संकट के समय महत्वपूर्ण सहारा प्रदान किया। संसाधन और श्रम का सामूहिक उपयोग महामारी से उत्पन्न आर्थिक झटके के प्रति एक प्रभावी प्रतिक्रिया सिद्ध हुआ।

फिर भी, पारंपरिक निर्वाह गतिविधियों पर निर्भरता क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार अवसरों की कमी दीर्घकालिक चुनौती बनी रही। सरकारी योजनाएँ सहायक रहीं, किंतु दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वयन संबंधी समस्याएँ स्पष्ट रहीं। सामुदायिक नेटवर्क — जैसे अनौपचारिक ऋण, श्रम-साझेदारी और सामूहिक खाद्य वितरण — संकट के समय सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्यरत रहे।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्तराखंड में परिवारों की आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। प्रत्यावर्ती प्रवासन ने ग्रामीण क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव डाला, किंतु पारंपरिक प्रथाओं और संयुक्त परिवार प्रणाली ने आंशिक सुरक्षा प्रदान की। राज्य की आर्थिक पुनर्प्राप्ति सीमित स्थानीय रोजगार अवसरों और राहत योजनाओं की पहुँच संबंधी चुनौतियों के कारण धीमी रही। नीति निर्माताओं को ग्रामीण अवसंरचना सुदृढ़ करने, कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य के संकटों में ग्रामीण समुदाय अधिक सशक्त और लचीले बन सकें।

संदर्भ सूची:

1. उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग। (2021). *कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण राज्य में लौटे प्रवासियों के आँकड़ों का विश्लेषण एवं सिफारिशें*। उत्तराखंड सरकार।
2. बिष्ट, आर. (2019). उत्तराखंड में बाह्य-प्रवासन और आर्थिक प्रभाव।
3. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी)। (2010)। *उत्तराखंड में श्रम प्रवासन और प्रेषण*। काठमांडू: आईसीआईएमओडी।
4. अबेला, एम. आई., एवं ससीकुमार, एस. के. (2020)। *कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों की आय हानि का आकलन*। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 63, 921–939। https://doi.org/10.1007/s41027-020-00281-y
5. अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। (2020)। *कोविड-19 और आजीविका संकट: लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट*। बेंगलुरु: अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय।
6. पाठक, एस. (2020)। *रिवर्स माइग्रेशन और कोविड-19: उत्तराखंड पर एक अध्ययन*। हल्द्वानी: उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय।
7. देसाई, ए. आर. (2018). भारत में परिवार संरचना और सामाजिक परिवर्तन।
8. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)। (2020)। *कोविड-19 महामारी और असंगठित प्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव*। नई दिल्ली: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।